पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 142

थाना कांड सं. -225 वर्ष- 2016 थाना- बिभूतिपुर जिला- समस्तीपुर, से उद्भूत

==========

मुकेश पासवान @ बिमलेश पासवान @ भगत जी, पिता- विशेश्वर पासवान, निवासी- गाँव- बाजितपुर

.....अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2019 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 153

थाना कांड सं. -225 वर्ष- 2016 थाना- बिभूतिपुर जिला- समस्तीपुर, से उद्भूत

==========

सुरेंद्र कुमार @ सुलेंद्र कुमार @ गोरे लाल, पिता- स्वर्गीय राम बहादुर, निवासी- गाँव- खानजाहपुर, थाना- चेरिया- बरियारपुर, जिला- बेगुसराय

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिती:

(2019 के आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 142 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री रणविजय आनंद, अधिवक्ता

सुश्री सरिता कुमारी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता: श्री सुजीत कुमार सिंह, स.लो.अभ

(2019 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 153)

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री रंजन कुमार झा, अधिवक्ता

श्री राणा प्रताप सिंह, अधिवक्ता

श्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

श्री विकास कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री सुजीत कुमार सिंह, स.लो.अभ

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- भारतीय दंड संहिता की धाराएं 363, 364 ए/34, 302/34, 201/34 और 302/120 बी
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 27

संदर्भित मामले:

- रामानंद @ नंदलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1396 में रिपोर्ट किया गया
- हरिचरण कुर्मी और जोगिया हजाम बनाम बिहार राज्य, 1964 एससीसी ऑनलाइन एससी 28 में रिपोर्ट किया गया
- सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2023) 11 एससीसी 255 में रिपोर्ट किया गया
- शरद बिरधीचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 में रिपोर्ट किया गया
- राज कुमार @ सुमन बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 609 में रिपोर्ट किया गया

अपील - यह अपील उस निर्णय को चुनौती देने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 364A/34, 302/34, 201/34 और 302/120B के तहत दोषी ठहराया गया है।

न्यायालय का निर्णय:

वर्तमान दो अपीलकर्ताओं का मुकदमा अलग-अलग सुनवाई में किया गया है, इसलिए सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान को इनके विरुद्ध प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो अपीलकर्ताओं को संबंधित घटना से जोड़ता हो। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत "अंतिम बार साथ देखे जाने" की थ्योरी भी उपरोक्त चर्चा के आधार पर स्वीकार नहीं की जा सकती। साथ ही, दूसरे अपीलकर्ता के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो उसे कथित घटना से जोड़ता हो। (पैरा 41)

प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति, जो अभियुक्त के विरुद्ध जाती है, उसे विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग-अलग अभियुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऐसा करने में विफलता एक गंभीर अनियमितता मानी जाएगी, जो मुकदमे को प्रभावित कर सकती है, यदि यह साबित हो जाए कि इससे अभियुक्त के अधिकारों को क्षति पहुँची है। (पैरा 45)

सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मृतक का शव मिलने की जो तथाकथित खोज हुई थी, उसे अभियुक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा, अभियुक्त को गवाहों द्वारा मृतक के साथ साइकिल पर अंतिम बार देखे जाने की जो परिस्थिति अभियोजन पक्ष ने रखी थी, वह भी अभियुक्त के समक्ष नहीं रखी गई। (पैरा 46)

अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास और संशोधन पाए गए हैं। अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण रूप से स्थापित करने में विफल रहा है। (पैरा 49)

अपील स्वीकार की जाती है। (पैरा 52)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

दिनांक: 18-02-2025

वर्तमान अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'दं.प्र.स.' के रूप में संदर्भित) की धारा-374 (2) के तहत दिनांकित 12.12.2018 के दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश दोनों को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भा.द.वि. की धारा-364 ए/34,302/34,201/34 और 302/120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और अपीलकर्ताओं को भा.द.वि. की धारा-364 ए/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माने का भुगतान न करने पर, प्रत्येक को छह महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, उन्हें भा.द.वि. की धारा-302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माना न भरने पर, प्रत्येक को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा, भा.द.सं. की धारा-201/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन्हें तीन साल के लिए कठोर कारावास की सजा और 2000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, प्रत्येक को एक महीने के लिए और कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा, उन्हें भा.द.सं. की धारा-302/120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

2. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री विजय आनंद को सुश्री सरिता कुमारी द्वारा सहायता प्रदान की गई (2019 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 142 में), श्री रंजन कुमार झा, अपीलार्थी के विद्वान वकील को श्री राणा प्रताप सिंह, मृत्युंजय कुमार मिश्रा और श्री विकास कुमार द्वारा सहायता प्राप्त (2019 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 153 में, और श्री सुजीत कुमार सिंह, विद्वान स.लो.अभ., दोनों मामलों में प्रत्यर्थी-राज्य के लिए को सुना।

3. चूंकि दोनों अपीलें एक ही निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं, अतः साथ सुनवाई कर इस उभयनिष्ठ निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

4. वर्तमान अपील दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

"सुचक कैलाश पासवान ने अपने पुत्र रौशन कुमार के लापता होने के संबंध में दिनांक 02.10.2016 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उनका पुत्र दिनांक 30.09.2016 को अपराह्न 02:00 बजे लापता हो गया था और उनके मोबाइल नंबर 9006122925 पर मोबाइल नंबर 8151957018 से एक कॉल आया था, जिसमें उनके पुत्र की सुरक्षित वापसी के लिए 15,00,000/- रुपये की फिरौती मांगी गई थी। जब उक्त मोबाइल फोन पर कॉल किया गया, तो उस तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और प्राथमिकी दर्ज होने तक उनके पुत्र का पता नहीं चला। "

5. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी ने जांच की और जांच के दौरान जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और उसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया जहां इसे सत्र परीक्षण संख्या 31/2017 के रूप में पंजीकृत किया गया।

6. इसके बाद, अभियुक्त व्यक्तियों का आगे का बयान संहिता की धारा-313 के तहत दर्ज किया गया और मुकदमे/विचारण के पूरा होने के बाद, निचली अदालत/सत्र न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया, जिसके खिलाफ अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपीलों को दायर किया है।

7. विद्वान अधिवक्ताओं ने सर्वप्रथम यह समर्पित किया कि प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब हुआ है तथा वास्तव में 30.09.2016 को घटित घटना के लिए सुचक द्वारा 02.10.2016 को लिखित शिकायत दी गई थी। यह भी समर्पित किया गया कि प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात भी उसकी प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को 06.10.2016 को ही भेजी गई,

जिसके लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यह भी समर्पित किया गया कि अपीलकर्ताओं का नाम प्राथमिकी में नहीं है।

8. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं का कहना है कि वर्तमान परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और विचाराधीन घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है जिनसे यह कहा जा सकता है कि वर्तमान अपीलार्थियों ने कथित अपराध किए हैं, जिसके बावजूद निचली अदालत ने दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश दर्ज किया है। यह आगे समर्पित किया जाता है कि अभियोजन-गवाहों के बयान में बड़े विरोधाभास, सुधार और विसंगतियां हैं और इसलिए, अभियोजन-गवाहों द्वारा दिए गए बयान को खारिज कर दिया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ताओं का कहना है कि अभियोजन पक्ष भी मृतक को मारने के आरोपी के उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा है। हालाँकि, विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह बताया गया है कि सुचक और आरोपी मुकेश पासवान के परिवार के साथ कोई विवाद नहीं था। वास्तव में, आरोपी मुकेश पासवान सुचक का भतीजा है। इस स्तर पर यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने सुचक से फिरौती के रूप में, 15,00,000/- रुपये की मांग की है। यह रिकॉर्ड में आया है कि सूचना देने वाला रेलवे का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है और वास्तव में, उसके पास भुगतान करने का कोई साधन नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि आरोपी मुकेश पासवान सुचक का भतीजा है। इसलिए, वह सुचक की खराब वित्तीय स्थिति से अवगत था और इसलिए, सुचक से, 15,00,000/- रुपये की मांग करने का कोई सवाल ही नहीं था, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

9. विद्वान अधिवक्ता आगे समर्पित करते हैं कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला सह-अभियुक्त मंटोश कुमार के इकबालिया बयान पर आधारित है, जिसका विचरण अलग किया गया क्योंकि उक्त आरोपी किशोर है। वर्तमान दो अपीलार्थियों पर अलग-अलग मुकदमा

चलाया गया है। विद्वान अधिवक्ताओं का यह भी तर्क है कि सह-अभियुक्त मंटोश कुमार का इकबालिया बयान भी वर्तमान अपीलार्थियों को बाध्य नहीं कर सकता है और केवल सह-अभियुक्त के उक्त इकबालिया बयान पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलार्थियों की दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता यह भी तर्क देते हैं कि अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष सी. डी. आर. को पेश करने में भी विफल हुआ है और यहां तक कि सी. डी. आर. भी साक्ष्य अधिनियम की धारा-65 बी (4) के तहत जारी किए गए किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में विधिवत साबित नहीं हुआ है। अभियुक्त सुरेंद्र कुमार उर्फ गोर लाल की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ताओं ने बताया है कि जाँच अधिकारी ने अपनी जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त सुरेंद्र कुमार से बरामद मोबाइल फोन को टेलीफोन विभाग से सत्यापित नहीं कराया था। इसके अलावा, अनुसंधानकर्ता, अ. सा. 11 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मृतक को साइकिल पर ले जाने की घटना का कोई गवाह नहीं है। विद्वान अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि अनुसंधानकर्ता ने आरोपी मुकेश कुमार से बरामद मोबाइल फोन के संबंध में डी. टी. ओ. के कार्यालय से यह सत्यापित नहीं किया कि उक्त मोबाइल उसके नाम पर है या उसके परिवार के सदस्य के नाम पर। विद्वान अधिवक्ता आगे कहते हैं कि का आगे का बयान दर्ज करते समय भी। संहिता की धारा-313 के तहत अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में सभी साक्ष्य उनके सामने नहीं रखे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप बचाव पक्ष के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है और इस तरह बचाव पक्ष को इसकी व्याख्या/स्पष्ट करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था।

10. इसलिए, विद्वान अधिवक्ताओं ने आग्रह किया कि आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द और निरस्त कर दिया जाए और इन दोनों अपीलों को स्वीकार कर लिया जाए।

11. अपने तर्क के समर्थन में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:-

1. **रामानंद @ नंदलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1396** में प्रकाशित:

2. **हरिचरण कुर्मी और जोगिया हाजम बनाम बिहार राज्य, 1964 में एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 28** में प्रकाशित:

3. **सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2023) 11 एस.सी.सी. 255** में प्रकाशित:

12. दूसरी ओर, विद्वान स.लो.अभ. ने इन दोनों अपीलों का विरोध किया है। विद्वान स.लो.अभ. मुख्य रूप से तर्क करते हैं कि हालांकि वर्तमान परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा कर लिया है और इस तरह आरोपी के खिलाफ मामले को उचित सन्देह से परे साबित कर दिया है। विद्वान स.लो.अभ. समर्पित करते है कि टेलीफोन नंबरों के संबंध में सुचक द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर, जांच की गई और सी. डी. आर. के आधार पर, यह पता चला कि फिरौती की मांग के लिए फ़ोन मंटोश कुमार के मोबाइल से की गई थी। अतः उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उक्त अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अन्य अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका का खुलासा किया। इसके अलावा, मंटोश कुमार के इकबालिया बयान के आधार पर, मृतक के शव/कंकाल की खोज की गई। इसके अलावा, वर्तमान अपीलार्थियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह आगे समर्पित किया जाता है कि अपीलकर्ताओं की ओर से सुचक से पैसे निकालने का एक उद्देश्य था और इसलिए, फिरौती की मांग की गई थी। हालांकि, इस बीच, आरोपी ने मृतक लड़के, यानी सुचक के बेटे की हत्या कर दी। इसलिए विद्वान स.लो.अभ. ने आग्रह किया कि अभिलेख पर पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं जिनसे यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने शुरू में लड़के का अपहरण किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। विद्वान ए.पी.पी. ने इसलिए आग्रह किया कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं जिससे कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने प्रारंभ में लड़के का अपहरण किया और उसके

बाद उसे मार डाला। इसलिए, विद्वत विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की है। यह भी समर्पित किया गया है कि यदि धारा-313 के तहत बयान दर्ज करते समय अभियुक्तों के समक्ष सभी आपत्तिजनक सामग्री और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे, तब भी अभियुक्तों को किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह न होने के कारण यह एक अनियमितता है और इसलिए उक्त अनियमितता का लाभ अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता।

13. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा समर्पित की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का भी अध्ययन किया है और प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य का भी अध्ययन किया है।

14. इस स्तर पर, हम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के प्रासंगिक अंश की सराहना करना चाहेंगे।

15. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने बारह गवाहों का परीक्षण किया।

16. अ.सा.- 1 बबीता देवी सुचक की बेटी है। उसने अपने मुख्य-परीक्षा में कहा है कि यह घटना एक साल पहले दोपहर 02:00 बजे हुई थी। उस दिन, वह कल्याणपुर में सुचक के घर पर थीं। उन्होंने/उसने आगे कहा है कि मुकेश पासवान (अपीलार्थी) आए और रौशन के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया कि वह मंदिर के पास खेल रहा था। इसके अलावा, उसने कहा है कि मुकेश ने उससे कहा कि वह रौशन के साथ दादू चौक जाएगा और वहाँ से वह रौशन को साइकिल के साथ वापस भेज देगा। इसके अलावा, उसने कहा है कि दो-तीन घंटे बाद भी रौशन घर नहीं लौटा, जिसके कारण उसने अपनी मां के साथ उसकी तलाश शुरू कर दी। वह आगे बताती है कि जब वह उक्त चौक पर पहुंची, तो उसे पता चला कि सुरेंद्र, मुकेश, संतोष और अनिल ने उसे (रौशन) मोटरसाइकिल पर ले गए और अगले दिन सुबह 6:00 बजे, उसके पिता (सुचक) के मोबाइल फोन नंबर 9006122925 पर एक कॉल किया गया

था जिसमें उसके बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए Rs.15,00,000/- की फिरौती की मांग की गई थी। इसके अलावा, उसने कहा है कि जब उक्त मोबाइल फोन पर आगे फिर से कॉल किया गया, तो उस तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दो दिन बाद उसे पता चला कि उसके भाई का शव चौक के पास पड़ा था।

16.1. अपनी जिरह के दौरान, उसने कहा कि उसके ससुराल वालों का स्थान बखोमल, बेगुसराय में है। वह अपने भाई दीपक की मृत्यु के बाद से अपने माता-पिता के घर में रहती है। उसने आगे कहा है कि यह घटना एक साल पहले 30.09 को हुई थी। उसे साल याद नहीं है। घटना का समय 02:00 शाम को था और उस समय वह अपने घर पर अकेली थी। दारोगाजी द्वारा पूछताछ के दौरान, उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने उसे सूचित नहीं किया था कि रोशन मुकेश के साथ जा रहा है। घटना के दो-तीन दिन बाद दारोगा जी उनके घर आए। उसने इस सुझाव का खंडन किया है कि उसने दारोगाजी के सामने यह खुलासा नहीं किया था कि मुकेश ने उसे बताया था कि उसने रौशन को दादू चौक से भेजा था और जब वह अपनी माँ के साथ उक्त चौक पर गई, तो उन्हें पता चला कि मुकेश, सुरेंद्र, संतोष और अनिल रोशन को मोटरसाइकिल पर ले गए और अगले दिन रौशन की सुरक्षित वापसी के लिए 15,00,000- रुपये की फिरौती की मांग करते हुए फोन किया गया। उसने आगे कहा कि आरोपी दो मोटरसाइकिलों पर सवार थे और उसने आरोपी को उक्त चौक से रोशन को ले जाते हुए नहीं देखा। उसने उक्त घटना के बारे में गवाही दी है जैसा कि उसने दादू चौक पर दूसरों से एकत्र किया था। उसने कहा कि वह दो दिन बाद शव देखने गई थी। उसने मृतक की पहचान उसकी जींस पैंट और ग्रीन शर्ट से की। वह आरोपी मुकेश के घर गई थी जहाँ उसके पिता और चाची आदि मौजूद थे। घटना की रात के दौरान किसी ने लड़के की तलाश नहीं की। मुखिया जी पुलिस स्टेशन गए थे और उनके पिता ने 01.10 पर अपने हस्ताक्षर किए थे। उसने इस बात से इनकार किया है कि चूंकि वह अपने ससुराल में रहती है, इसलिए उसे अपने माता-पिता के घर के मामलों के बारे में पता नहीं है और उसने दूसरों

के निर्देश के अनुसार झूठ बोला है और कि मुकेश अपने पेशे के संबंध में घटना के समय बाहर था और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है।

17. अ.सा. 2 शांति देवी सुचक की पत्नी हैं। उसने कहा है कि घटना अपराह्न 02:00 बजे हुई थी। वह कल्याणपुर गई थी। लौटते समय जब वह दादू चौक पहुंची तो उसने देखा कि आरोपी मुकेश पासवान साइकिल पर उसके 10 साल का बेटे को ले जा रहा था। जब वह घर आई तो उसने अपनी बेटी से लड़के के बारे में पूछा। जब लड़का डेढ़ घंटे तक वापस नहीं आया तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह नहीं मिला। दादू चौक पर मौजूद लोगों ने कहा कि तीन लोग लड़के को मोटरसाइकिल पर ले गए थे। जब उनके पति अपराह्न 04:00 बजे आए, तो उन्होंने भी लड़के के बारे में पूछा। उसकी बेटी ने कहा कि मुकेश लड़के को अपने साथ ले गया था। इसके बाद, उसके पति को एक फोन आया जिसमें लड़के की सुरक्षित वापसी के लिए फिरौती के रूप में Rs.15,00,000/- की मांग की गई।

17.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि दारोगाजी ने उसका बयान दर्ज किया था। उसने कहा है कि मुकेश और वह एक ही आंगन साझा करते हैं क्योंकि मुकेश उसके पति के बड़े भाई का बेटा है। मुकेश और रौशन की कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही मुकेश के माता-पिता की कोई दुश्मनी थी। उसने मुकेश को दोपहर 02:00 साइकिल के वाहक (कैरियर) पर अपने बेटे को ले जाते देखा था। हालाँकि उसने रोशन को मुकेश के साथ जाते देखा था, लेकिन उसने उसे मना नहीं किया क्योंकि मुकेश उसका भाई था। उसने आगे कहा है कि पहले भी उसका बेटा घर से बाहर जाता था, लेकिन वह वापस आ जाता था। कभी-कभी वह छात्रावास भी छोड़ चुका था। उसके अलावा किसी ने भी लड़के (उसके बेटे) को मुकेश द्वारा साइकिल पर ले जाते हुए नहीं देखा था। उसने अपने बेटे को मुकेश द्वारा ले जाने की घटना का खुलासा किसी को नहीं किया था। खोजबीन/तलाशी के दौरान, दादु चौक के अज्ञात राहगीरों द्वारा उसे बताया गया कि मुकेश और दो अन्य उस लड़के को मोटरसाइकिल पर ले गए, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कहाँ गए थे। वह दोपहर 3:00 बजे घर लौटी

और मुकेश के बारे में अपने पति को बताया। उसने पाँच दिनों के बाद 05.10 बजे अपने बेटे का शव देखा। शव टुकड़ों में कटा हुआ था। केवल धड़ (ट्रंक) मांस के अवशेष के साथ पड़ा हुआ था। जब उसने धड़ को गले लगाया, तो खून नहीं बह रहा था। घटना स्थल के पास खून बिखरा हुआ था। गन्ने (गन्ने के खेत) तोड़े और कुचले गए थे। उसने कपड़ों से शव की पहचान/शिनाख्त की। उन्होंने मुकेश को गलत तरीके से फंसाने और गलत सबूत देने के सुझाव से इनकार किया है।

18. अ.सा. 3 नारायण पासवान एक स्वतंत्र संयोगवश गवाह हैं। उन्होंने कहा है कि घटना लगभग 13 महीने पहले दोपहर 02:00 बजे की है। उस समय पर वे अपनी बेटी विमला देवी को लेने दादू चौक गए थे, जब उन्होंने देखा कि मुकेश पासवान को कैलाश पासवान के बेटे अर्थात् रौशन पासवान को साइकिल पर लेते हुए देखा। दादू चौक पर दो मोटरसाइकिलें खड़ी थीं और प्रत्येक मोटरसाइकिल पर दो लोग सवार थे। वहाँ से वे रोशन को मोटरसाइकिल पर ले गए। उन्होंने रौशन का शव देखा था जिससे बदबू आ रही थी। उन्होंने और कैलाश ने शव की पहचान की। वह अदालत में मौजूद आरोपी मुकेश की पहचान करता है।

18.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि उन्हें सुनने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया है कि उन्होंने दारोगाजी को यह नहीं बताया था कि यह घटना दोपहर 02:00 बजे हुई थी और कि जब वह अपनी बेटी को लेने गए थे तो उन्होंने मुकेश पासवान को कैलाश पासवान के बेटे को साइकिल पर ले जाते देखा था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें इस तरह की घटना की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी और न ही ऐसी कोई घटना हुई थी।

19. अ.सा. 4 उपेंद्र पासवान भी एक स्वतंत्र संयोगवश गवाह हैं। उसने कहा है कि जब वह पंचायत भवन से लौट रहा था, तो उसे मुकेश पासवान को साइकिल पर कैलाश

पासवान के बेटे को ले जाते हुए देखने का मौका मिला, लेकिन वह घर चला गया। खोजबीन करने पर, लड़के का पता नहीं चल सका। घटना के दो दिन बाद उन्हें पता चला कि लड़के का शव चेरिया बरियारपुर के गोबारी चौर में मिला है। उसे पता चला कि लड़के की सुरक्षित वापसी के लिए 15,00,000/- रुपये की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन उसे पूरा न करने पर लड़के को मार दिया गया। वह अदालत में मौजूद आरोपी की पहचान करता है।

19.1. अपनी जिरह में, उन्होंने कहा है कि जिस तारीख को लड़का लापता हुआ था, उस दिन नरेशजी ने 20-25 व्यक्तियों की उपस्थिति में पुलिस स्टेशन में उनका बयान दर्ज किया था। उन्होंने आगे कहा है कि उनकी कैलाश पासवान से कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने इस घटना के बारे में कैलाश पासवान की पत्नी को छोड़कर किसी से भी से चर्चा नहीं की थी। कैलाश पासवान कोई साधन संपन्न व्यक्ति नहीं हैं और वह किसी तरह अपनी नौकरी से होने वाली कमाई से अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उन्होंने झूठे सबूत देने के सुझाव से इनकार किया है।

20. अ.सा. 5 रामचंद्र पासवान एक जब्ती-सूची गवाह हैं। उसने जब्त किए गए सैमसंग मोबाइल (प्रदर्श-1) की जब्ती-सूची में अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसे नहीं पता है कि और किसने जब्ती-सूची में उसके हस्ताक्षर किए थे। वह अपने हस्ताक्षर करने के बाद वहाँ से चला गया। उन्होंने झूठे सबूत देने के सुझाव से इनकार किया है।

21. अ. सा. 6 भीखन पासवान एक सुनी-सुनाई/अनुश्रुत गवाह हैं। उन्होंने बस इतना कहा है कि उन्हें शाम को पता चला कि मुकेश रोशन को अपनी साइकिल पर ले गया और वापस नहीं आया। अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि उन्हें घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है।

22. अ.सा. 7 कैलाश पासवान सुचक हैं। उन्होंने अपने मुख्य-परीक्षा में कहा है कि घटना दोपहर 02:00 बजे हुई थी। वे शाम 04:00 बजे ड्यूटी से आए थे। रोशन घर पर नहीं

था। जब उसने अपनी बेटी बबीता कुमारी से रौशन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मुकेश उसे दादू चौक ले गया था। तलाश करने पर, उसका पता नहीं चल सका। बबीता ने यह भी कहा कि उनकी माँ कल्याणपुर गई थीं। जब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, उसने कहा कि उसने मुकेश को साइकिल पर दादू चौक के पास रौशन को ले जाते देखा था। इसके बाद वह घर लौट आयी। घटना के दिन उसका बेटा वापस नहीं आया। अगले दिन उसे मोबाइल नंबर 8151957018 से अपने मोबाइल नंबर 9006122925 पर फिरौती के लिए अनजान फोन आया और उसने अपने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए 15,00,000/- रुपये की मांग की। उन्होंने मुखिया जी द्वारा लिखित शिकायत का मसौदा तैयार कराया, उस पर अपने हस्ताक्षर किए और पुलिस स्टेशन में समर्पित किया। उन्होंने अपने हस्ताक्षर (प्रदर्श-2) की पहचान कर ली है। मामला दर्ज होने के बाद, पुलिस उसके घर आई थी और उससे पूछताछ की और उसका बयान और उसकी बेटी और पत्नी का बयान भी दर्ज किया। पाँच दिन बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. ने उसे गोबारी चौर आने के लिए कहा। वह, उसकी पत्नी और बेटी वहाँ गए। इतने सारे लोग पहले से ही वहाँ थे। उनके बेटे का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने जींस के पैंट से अपने बेटे का बताया था। शरीर टुकड़ों में कटा हुआ और बिना सिर वाला था। वह उन अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान करने का दावा करता है जिनमें से मुकेश और सुरेंद्र उर्फ गोरे लाल अदालत में मौजूद हैं।

22.1. अपनी जिरह में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा था। उनकी गोरे लाल से कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही उनके उनसे बातचीत करने के संबंध थे। उन्होंने लिखित शिकायत में अभियुक्तों के नाम नहीं दिए थे। वह आगे कहता है कि उसने केवल मुकेश का नाम दिया था और किसी और का नहीं।

22.2. अभियुक्त मुकेश की ओर से अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि मुखिया जी ने पुलिस स्टेशन में उनके द्वारा समर्पित लिखित शिकायत का मसौदा तैयार किया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने केवल मोबाइल नंबर 8151957018 के मालिक का

नाम लिखा था, बल्कि उन्होंने आरोपी मुकेश का नाम भी दिया था। उन्होंने आगे कहा है कि उनके बेटे का शव 05.10.2016 को यानी घटना के पांच दिनों के बाद पाया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उपेंद्र और नारायण पासवान ने मुकेश को उसके बेटे को अपने साथ ले जाते देखा था। उसकी मुकेश या उसके पिता से कोई दुश्मनी नहीं है। वह और मुकेश एक ही आंगन साझा करते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे को दोपहर 02:00 बजे साइकिल पर ले जाया गया था जिसे उनकी बेटी और उनकी पत्नी ने देखा था। पुलिस स्टेशन जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से बात की थी। जब उसका बेटा वापस नहीं आया, तो उसने मुकेश के पिता से पूछा जब मुकेश की पत्नी ने कहा कि मुकेश भी वापस नहीं आया है। पुनः 08:00 बजे शाम को वह मुकेश के घर गया और फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मुकेश वापस नहीं आया है। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया है कि उन्होंने एक सुनी-सुनाई गवाह के रूप में गवाही दी है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने केवल संदेह के आधार पर यह मामला दर्ज किया है।

23. अ.सा. 8 नवीन कुमार पंडित एक जब्ती-सूची गवाह है। उसने कहा है कि उसने आरोपी अनिल कुमार से आइडिया और टाटा डोकोमो के सिम वाले जब्त किए गए कार्बन स्क्रीन टच मोबाइल की जब्ती-सूची में अपने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने जब्ती-सूची (प्रदर्श-3) पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है। उसने आरोपी सुरेंद्र कुमार उर्फ गोर लाल के घर से जब्त किए गए चांदी के रंग के केचाओड़ा मोबाइल की जब्ती सूची पर भी अपने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने जब्ती-सूची (प्रदर्श-3/1) पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है। उसने एयरटेल और रिलायंस के सिम वाले जब्त किए गए काले रंग के केचोड़ा डी. ए. मोबाइल की जब्ती सूची में भी अपने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने अपने हस्ताक्षर की पहचान प्रदर्श-3/2 के रूप में की है।

23.1. आरोपी मुकेश की ओर से अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसका बयान पुलिस के सामने दर्ज नहीं किया गया था। उन्होंने एक खाली कागज पर अपने हस्ताक्षर

किए थे। अभियुक्त गोरे लाल की ओर से अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसने तीन-चार खाली कागजों पर अपने हस्ताक्षर किए थे। जब पुलिस ने हस्ताक्षर किए, तो उसके सामने कोई मोबाइल नहीं रखा गया और न ही उसकी उपस्थिति में किसी आरोपी की तलाशी ली गई।

24. अ.सा. 9 अंजनी कुमार सिंह भी एक जब्ती-सूची गवाह है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अ.सा. 8 द्वारा वर्णित वस्तुओं की जब्ती-सूची पर भी अपने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने अपने हस्ताक्षरों की पहचान प्रर्दश क्रमशः 3/4, 3/5 और 3/6 के रूप में की है।

24.1. अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने अ.सा. 8 द्वारा दिए गए संस्करण को दोहराया है।

25. अ.सा. 10 संजीत कुमार ने गवाही दी है कि 21.12.2016 को उन्हें एस. एच. ओ., बिभूतिपुर के रूप में तैनात किया गया था। दिनांक 02.10.2016 को, उन्होंने सी. एस. कुमार से 2016 के बिभूतिपुर पी. एस. केस संख्या 225 की जांच का प्रभार संभाला। पुलिस रिकॉर्ड में उन्हें मुकेश कुमार और गोरे लाल की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं मिली। जाँच पूरी होने के बाद, उन्होंने भा. द. सं. की धारा-364ए, 302, 201, 120बी /34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी मंटोश कुमार और सुरेंद्र कुमार उर्फ सुलेंद्र कुमार उर्फ गोर लाल, अनिल कुमार और मुकेश पासवान के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया।

25.1. अपनी जिरह में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जांच के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री एकत्र नहीं की और उन्होंने अपने पूर्ववर्ती द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर अपने वरिष्ठ के निर्देश पर प्राथमिकी नामित आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया।

26. अ.सा. 11 चतुर्वेदी सुधीर कुमार ने अपने बयान में कहा है कि 02.10.2016 को उन्हें एस. एच. ओ., बिभूतिपुर पी. एस. के रूप में तैनात किया गया था। उन्होंने भा.द.सं. की धारा 363,364ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए सुचक राम कैलाश पासवान द्वारा समर्पित लिखित रिपोर्ट के आधार पर 2016 का बिभूतिपुर पी. एस. मामला संख्या 225

दिनांक 02.10.20216 को दर्ज किया। वह अपने हस्ताक्षर वाले और अपने द्वारा पृष्ठबद्ध किए गए लिखित आवेदन की पहचान (प्रदर्श-2/1) करता है। वह औपचारिक प्राथमिकी पर अपने हस्ताक्षर की पहचान (प्रदर्श-4) करता है। उन्होंने सी. डी. आर. और मोबाइल नंबर 8151957018 के स्थान का अध्ययन किया, जिससे उन्हें पता चला कि जिस मोबाइल से फिरौती मांगी गई थी, उस पर सिम नंबर 8151957018, आई.एम.ई.आई. नंबर 868903020284804 था। उक्त मोबाइल के मालिक का मोबाइल नंबर 9199202290 के मालिक से परिचय था। इसलिए इस प्रकार, मोबाइल नंबर 9199202290 के मालिक का पता लगाना आवश्यक था। दोनों मोबाइल नंबरों और सबसे आम/सामान्य संपर्क संख्या 9102840568 के सी. डी. आर. के विश्लेषण पर यह पता चला कि जिस नंबर से फिरौती की मांग की गई थी, वह खानजाहपुर, पी. एस. चेरिया बरियारपुर, जिला-बेगुसराय में था। घटना के बाद से, मोबाइल नंबर 9102840568 और 9199202290 के बीच नियमित कॉल आ/हो रहे हैं जो अभी भी जारी है। जब उन्हें बताया गया कि मोबाइल नंबर 8151957018 से फिरौती मांगी गई है, तो उन्होंने उक्त नंबर पर डायल किया, जब उस नंबर के मालिक ने जवाब दिया कि वह मैंगलोर में रहते हैं और उन्होंने किसी से बात नहीं की है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि कैलाश पासवान को घटना के संबंध में एक लिखित शिकायत समर्पित करनी चाहिए और अपना बयान दर्ज कराना चाहिए, जिसके बाद कैलाश पासवान पुलिस स्टेशन आए और लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर उन्होंने बिभूतिपुर पी. एस. केस नंबर 225/2016 दिनांक 02.10.2016 को दर्ज किया और जांच शुरू की। जाँच के दौरान, वह राम प्रताप महतो के घर गया और मोबाइल नंबर 9199202290 के मालिक के बारे में पूछा, जिस पर मंटोश कुमार ने कहा कि यह उसका मोबाइल फोन है और कि वह राम प्रताप महतो का बेटा है। दो गवाहों अंजनी कुमार सिंह और नवीन कुमार की उपस्थिति में उसने उस मोबाइल फोन की जब्ती-सूची तैयार की, जिस पर/में एयरटेल सिम नंबर 7482979565 भी था और उसी की एक प्रति मंटोश कुमार को

सौंपी और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने आरोपी मंटोश कुमार का इकबालिया बयान भी दर्ज किया जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने जब्ती सूची (प्रदर्श-3/8) में चेरिया बरियारपुर के पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर की पहचान की थी। उन्होंने आगे कहा है कि एफ़. आई. आर. के आरोपी मंटोश कुमार द्वारा दिए गए सुराग पर वह घटना स्थल पर गया जो *गुआबारी चौर* में स्थित *भगवानक* कुएँ के पास है जहाँ दुर्गंध आ रही थी। जब वह गन्ने के एक बड़े खेत के पश्चिमी हिस्से के पास पहुंचे तो दुर्गंध बढ़ गई जिससे यह स्पष्ट हो गया कि रोशन कुमार का शव उस जगह के आसपास कहीं पड़ा हुआ है। बाद में, बिना सिर और पैर के एक शव सड़ी हुई हालत में जींस, फुल पैंट पहने हुए पाए गए, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर, पुलिस निरीक्षक, रोसेरा और लापता लड़के रौशन कुमार के पिता को दी। लापता बच्चे रौशन कुमार के पिता कैलाश पासवान वहां पहुंचे और शव पर लगे कपड़ों की मदद से शव की पहचान अपने बेटे के होने की पहचान की। चेरिया बरियारपुर पी. एस. के पुलिस अधिकारी शंभू शर्मा द्वारा शव की जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर किए थे। घटना स्थल से कुछ दूरी पर, सिर ऐसा पाया गया जैसे कि सियार या जंगली जानवरों द्वारा आंशिक रूप से खाया गया हो। इसके बाद, उन्होंने सुरेंद्र कुमार @गोरेलाल के घर पर छापा मारा और 9102840568 और 8431785255 नंबर वाला कचैदो मोबाइल बरामद किया। उन्होंने उसी की जब्ती सूची तैयार की (प्रदर्श-एम/1)। उन्होंने गोरेलाल के घर से मोबाइल नंबर 7654613804 भी बरामद किया (प्रदर्श-एम/2)। मंटोश कुमार के इकबालिया बयान के आधार पर उसने अनिल कुमार के घर पर छापा मारा और दो सिम वाले कार्बन मोबाइल यानी 8651977240 और 8904710763 (प्रदर्श-एम/3) बरामद किए और आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार किया। सभी एफ़. आई. आर. अभियुक्त व्यक्तियों से एक के बाद एक पूछताछ की गई और उन सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि मुकेश पासवान @ विमलेश पासवान के पास था। उसके चचेरे भाई रौशन कुमार का अपहरण कर लिया था और उसके निर्देश पर उन्होंने उसे मारने की धमकी

देते हुए फिरौती मांगी। इसके बाद उसने मुकेश पासवान @विमलेश पासवान @साधु @भगत के घर पर छापा मारा और 9525816772 नंबर वाला एक काले रंग का एक सैमसंग मोबाइल (प्रदर्श-एम/4) बरामद किया। उसने एफ़. आई. आर. के आरोपी मुकेश पासवान उर्फ विमलेश कुमार को गिरफ्तार किया और उसका बयान दर्ज किया जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल किया और कहा कि वह पारिवारिक झगड़े के कारण अपने चचेरे भाई रौशन कुमार को मारना चाहता था और उसने मंटोश कुमार और सुरेंद्र कुमार उर्फ गोरेलाल के साथ बैंगलोर में ही इसके लिए योजना बनाई। उनकी योजना के अनुसार, 30.09.2016 को मुकेश कुमार अपने चचेरे भाई रौशन कुमार को चेरिया बरियारपुर ले गया और उसे मंटोश कुमार और गोरेलाल उर्फ सुरेंद्र कुमार को सौंप दिया। वे उसे मंटोश कुमार के घर ले गए और मुकेश अपने घर लौट आया। कुछ बच्चों ने मुकेश को रोशन कुमार को अपनी साइकिल पर ले जाते देखा था, जिसके कारण कैलाश पासवान ने उनसे रौशन कुमार के ठिकाने के बारे में पूछा। मुकेश ने जवाब दिया कि रौशन कुमार दहुल चौक के सेंट जेवियर स्कूल के पास उसकी साइकिल से उतर गया। दिनांक 01.10.2016 को, गोरेलाल और मंटोश कुमार ने गोरेलाल के मोबाइल फोन से 15,00,000/- रुपये की फिरौती की मांग की। इस पर, मुकेश ने रोशन कुमार को मारने का आदेश दिया और फिर पैसे की मांग की जैसे कि वह जीवित है, साजिश प्रकाश में आएगी। अनिल कुमार सहित वे लड़के को गन्ने के खेत में ले गए, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को 01.10.2016 पर फेंक दिया। लेकिन जब मंटोश को गिरफ्तार किया गया तो उसके बयान पर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। विमलेश पासवान ने भी केस डायरी में अपने हस्ताक्षर किए।

26.1 अपनी जिरह में, आरोपी मुकेश पासवान @ विमलेश की ओर से, उसने कहा है कि उसने मुकेश से बरामद मोबाइल फोन को डी.टी.ओ. से सत्यापित नहीं कराया है। उन्होंने मुकेश से बरामद मोबाइल नंबर 9525816772 के संबंध में कोई दस्तावेज जब्त नहीं किया। मुकेश की गिरफ्तारी से पहले ही मंटोश ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और पूरी

घटना के पीछे की साजिश का खुलासा कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने धारा 164 दं.प्र.सं के तहत अपना अपराध स्वीकार करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों का बयान दर्ज कराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह भी कहा है कि मोबाइल फोन के टावर स्थान (लोकेशन) और सी. डी. आर. के आधार पर साजिश का पता चला और वैज्ञानिक जांच के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आगे कहा है कि मुकेश द्वारा मृतक को साइकिल पर चेरिया बरियापुर ले जाने की घटना का कोई गवाह नहीं है। अभियुक्त के अलावा, किसी अन्य गवाह ने यह नहीं बताया कि मुकेश मृतक को साइकिल पर ले गया था। मृतक के पिता ने अपने बयान में कहा था कि मृतक ने एक बार स्कूल छोड़ दिया था।

26.2 अपनी जिरह में, आरोपी सुरेंद्र महतो @गोरेलाल की ओर से उसने कहा है कि उसने गोरेलाल के दो मोबाइल फोन जब्त किए थे और उसी की जब्ती सूची की एक प्रति गोरेलाल को सौंपी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं और साथ ही आरोपी के हस्ताक्षर भी हैं। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने सुरेंद्र से बरामद मोबाइल फोन को टेलीफोन विभाग से सत्यापित नहीं कराया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने एक त्रुटिपूर्ण जांच की है।

27. अ.सा.- 12 डॉ. रवि ने अपने मुख्य-परीक्षा में कहा है कि, 07.10.2016 को, उन्हें दरभंगा मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग में एक शिक्षक के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन, उन्होंने धातु के डिब्बे में रखी प्लास्टिक की चादरों में रोशन कुमार के कंकाल के अवशेष प्राप्त किए और निम्नलिखित टिप्पणियों को नोट कियाः

> "डिब्बे को खोलने पर छाती पर कुछ मांसपेशियों के लगाव के साथ कंकालयुक्त मृत शरीर, दोनों ऊपरी अंग और निचले अंग और कूल्हे से दुर्गंध निकल रही थी। सिर (खोपड़ी) जांच के लिए उपलब्ध नहीं था। पेट और वक्ष विसरा का चिपका हुआ हिस्सा दुर्गंध के साथ उपलब्ध थे।

निम्नलिखित हड्डियों की पहचान की गईः-

फेमर-2 टिबिया-2, (कशेरुकाएँ)वर्टेब्रा-ऑल सेक्रम-1, ह्यूमरस-2 रेडियस-2, (कूल्हे की हड्डी)हिप बोन-2, उल्ना-2.

(i) उत्पत्ति के बारे मेंः उपलब्ध हड्डियाँ मानव शरीर रचना विज्ञान की पुष्टि करती हैं और कोई दोहराव नहीं था।

(ii) यौन संबंध के बारे मेंः ग्रेटर सियाटिक नॉच संकीर्ण और गहरा था, सब प्यूबिक एंगल तीव्र था। सेक्रम संकीर्ण था, समान रूप से वितरित वक्रता और अच्छी तरह से चिह्नित त्रिक प्रोमोन्टरी के साथ लंबा था। प्रथम सैक्रल वर्टेब्रा(कशेरुका) बड़ी थी।

(iii) आयु के बारे मेंः इस्कियोप्यूबिक रामी आपस में जुड़े हुए पाए गए। दोनों एसिटेबुलर गुहाओं का ट्राइरेडिएट उपास्थि प्रकट नहीं हुआ था। दोनों ह्यूमरस के मध्य और पार्श्व एपिकॉन्डाइल्स का केंद्र दिखाई दिया लेकिन फ्यूज नहीं हुआ। सभी सैक्रल (त्रिक) कशेरुकाएँ एक दूसरे के साथ एकजुट नहीं थीं। दोनों फीमर के छोटे ट्रोकैंटरों के ऑसिफिकेशन(अस्थिकरण) का केंद्र दिखाई नहीं दिया।

(iv) चोट के बारे मेंः उपलब्ध हड्डियों में से किसी पर भी चोट का कोई निशान नहीं पाया जा सका। पेट और वक्ष विसरा की संरक्षित चिपकी हुई सामग्री(पदार्थ) को बॉयम में सामान्य नमक के एस/एस (सॉल्यूशन/घोल) में ठीक से लेबल किया गया और मेडिकोलेगल सील के साथ सील कर दिया गया और यदि आवश्यक हो, तो आगे की जांच के लिए एफ.एस.एल. बिहार पटना को भेजे जाने के लिए इस मामले के उसी अनुसंधानकर्ता को संचरण/भेजे जाने के लिए साथ आए चौकीदार 2/1 उमाकांत साह को सौंप दिया गया।

रायः कंकाल के अवशेष लगभग 10-12 वर्ष (दस से बारह वर्ष) की आयु के पुरुष के थे। मौत के कारण का पता नहीं चल सका है। समय बीत गया - क्योंकि मृत्यु परीक्षा के समय से 5 से 7 दिनों के भीतर प्रतीत होती है। जैसा कि कहा गया है, संरक्षित विसरा का उपयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा आवश्यकता पड़ने पर आगे की जांच के लिए किया जा सकता है।

27.1. अपनी जिरह में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने डी. एन. ए. परीक्षण नहीं किया/कराया था क्योंकि इसकी मांग नहीं की गई थी। उन्होंने शव को वापस नहीं किया था और उसका निपटान नहीं किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया।

28. हमने पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकीलों द्वारा प्रचार/समर्पित की गई दलीलों पर विचार किया है, अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष के नेतृत्व में/द्वारा समर्पित पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना (पुनर्मूल्यांकन) की है और पेपर-बुक और ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

29. सुचक द्वारा दिए गए प्राथमिकी से यह पता चलेगा कि सुचक के मामले के अनुसार, उसका 10 साल का बेटा 30 सितंबर, 2016 को अपराह्न 02:00 बजे से लापता था। इसके अलावा, 01.10.2016 को लगभग सुबह 06:45 बजे सुचक से 15,00,000/- (पंद्रह लाख) रुपये की फिरौती की मांग की गई थी। हालाँकि, लिखित शिकायत पुलिस को 02.10.2016 को लगभग 12:30 बजे दी गई थी शुरुआत में, प्रथम सुचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 364 ए के तहत अपराध करने के लिए दर्ज किया गया था, सुचक ने किसी भी व्यक्ति पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया है। इस प्रकार, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई थी। यह रिकॉर्ड से आगे पता चलेगा कि 02.10.2016 को प्रथम सुचना रिपोर्ट के पंजीकरण के बाद भी, जांच एजेंसी ने इसे 06.10.2016 को संबंधित

मजिस्ट्रेट को भेजा। इस प्रकार, विद्वान मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रति भेजने में देरी हुई है।

30. यह अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से आगे पता चलेगा कि विचाराधीन घटना जिसमें अपहरण की घटना और सुचक के बेटे को ले जाने की घटना शामिल है का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है,। अतः अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने मृतक के करीबी रिश्तेदारों सहित 12 गवाहों से पूछताछ की थी। मृतक की बहन अ. सा. 1 द्वारा दिए गए बयान से यह पता चलता है कि उसका मामला यह है कि आरोपी मुकेश पासवान, जो उसका चचेरा भाई है, उक्त गवाह के स्थान पर आया और रौशन (मृतक) के बारे में पूछताछ की। उसका मामला यह है कि उसने जवाब दिया कि उसका भाई (रौशन) मंदिर के पास खेल रहा था और इसलिए, मुकेश ने उससे कहा कि वह रौशन के साथ दादू चौक जाएगा और वह रौशन को साइकिल से वापस भेज देगा।

30.1. इसी तरह, मृतक की माँ अ. सा. 2 शांति देवी ने भी अदालत के समक्ष कहा है कि वह कल्याणपुर गई थी। हालाँकि, उक्त स्थान से अपने घर लौटने के समय, जब वह दादू चौक पहुंची, तो उसने देखा कि आरोपी मुकेश पासवान उसके 10 साल के बेटे को साइकिल पर ले जा रहा था। अ.सा. 3 नारायण पासवान, जो एक स्वतंत्र गवाह हैं, ने कहा है कि प्रासंगिक समय पर वह अपनी बेटी विमला देवी को लेने के लिए दादू चौक गया था। उस समय उन्होंने मुकेश को कैलाश पासवान (सुचक) के बेटे को साइकिल पर ले जाते देखा। इसी तरह का संस्करण अ.सा. 4 उपेंद्र पासवान का भी है, जो एक स्वतंत्र गवाह भी हैं। इसके अलावा, सुचक ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि शिकायत मुखिया द्वारा लिखी गई थी और उसने केवल उस पर हस्ताक्षर किए हैं। हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा मुखिया का परीक्षण नहीं कराया गया है।

30.2. हालाँकि, यह ध्यान रखना उचित है कि अ. सा. 1 द्वारा अ. सा. 4 को दिए गए उपरोक्त संस्करण पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कुछ और नहीं बल्कि उक्त गवाहों के बाद के विचार और एक बेहतर संस्करण है। इस स्तर पर, यदि सूचनादाता द्वारा दी गई लिखित शिकायत को ध्यान से देखा जाता है, तो यह पता चलता है कि कथित घटना के लिए जो 30 सितंबर, 2016 को लगभग 02:00 बजे दोपहर को हुई थी और 01.10.2016 को 06:45 बजे शाम को की गई फिरौती की मांग के लिए, 02.10.2016 को 12:30 बजे दोपहर को लिखित शिकायत दी गई। इस प्रकार, लिखित शिकायत दो दिन बाद दी गई। मृतक के पिता अर्थात सुचक द्वारा दी गई लिखित शिकायत में संबंधित समय पर मृतक रोशन के साथ मुकेश पासवान को साइकिल पर देखने की घटना के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है। दो दिन की अवधि के बाद भी किसी ने भी इसका खुलासा नहीं किया है कि मृतक को आखिरकार मुकेश पासवान के साथ साइकिल पर देखा गया था। अ.सा. 1, जो मृतक की बहन है, और अ.सा. 2, जो मृतक की मां है, अगर उन्हें मुकेश के मृतक को साइकिल पर ले जाने के तथ्य के बारे में पता होता, तो स्वाभाविक रूप से, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करते समय सुचक के साथ-साथ पुलिस को भी उक्त पहलू के बारे में खुलासा किया होता। यहां तक कि तथाकथित दो स्वतंत्र गवाहों ने भी संबंधित समय पर उक्त पहलू के बारे में खुलासा नहीं किया और इसलिए, अ. सा. 3 और अ. सा. 4 केवल संयोगवश गवाह हैं।

31. अभियोजन पक्ष द्वारा समर्पित उपरोक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यदि अ.सा. 11, अनुसंधानकर्ता द्वारा दिए गए बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि सुचक द्वारा दिए गए मोबाइल फोन नंबर के विवरण के आधार पर, अनुसंधानकर्ता ने सी. डी. आर. एकत्र किया और उक्त विवरणों का आवश्यक विश्लेषण करने के बाद, अनुसंधानकर्ता ने आरोपी मंटोश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह आगे पता चलता है कि सह-आरोपी मंटोश कुमार द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर मृतक के शव/कंकाल की खोज की गई थी। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि सह-अभियुक्त

मंटोश कुमार ने अपने इकबालिया बयान में अन्य अभियुक्तों के नाम और जिस तरह से उन्होंने कथित अपराध किए हैं और उसके बाद अपीलार्थी/अभियुक्त मुकेश पासवान @ बिमलेश पासवान @ भगतजी गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह, अन्य अपीलार्थी सुरेंद्र कुमार उर्फ गोर लाल को भी सह-अभियुक्त मंटोश कुमार द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

32. यह अ.सा. 11, अनुसंधानकर्ता की प्रतिपरीक्षा से आगे पता चलेगा कि उसने डी.टी.ओ. के कार्यालय से अपीलार्थी मुकेश से जब्त किए गए मोबाइल फोन के बारे में सत्यापित नहीं किया कि क्या उक्त मोबाइल मुकेश या उसके परिवार के सदस्य के नाम पर था। उन्होंने उक्त मोबाइल फोन के संबंध में कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया। जाँच अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया कि मुकेश पासवान की गिरफ्तारी से पहले ही मंटोश का इकबालिया बयान दर्ज किया जा चुका था। इसके अलावा, जिरह के पैरा-24 में अनुसंधानकर्ता ने स्वीकार किया कि मुकेश द्वारा मृतक को साइकिल पर ले जाने की घटना का कोई गवाह नहीं है। इसी तरह, उसकी जिरह के पैरा 33 में अ.सा. 11 ने स्वीकार किया है कि आरोपी सुरेंद्र कुमार से दो मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। हालांकि, उन्होंने सुरेंद्र कुमार से बरामद मोबाइल फोन को टेलीफोन विभाग से सत्यापित नहीं कराया था।

33. इस प्रकार, अनुसंधानकर्ता, अ.सा. 11 द्वारा दिए गए उपरोक्त साक्ष्य से यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई गवाह नहीं था जिसने मुकेश को मृतक को अपनी साइकिल पर ले जाते देखा हो। इसके अलावा, हालाँकि अपीलार्थी मुकेश के साथ-साथ अपीलार्थी सुरेंद्र कुमार से मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे, लेकिन अनुसंधानकर्ता द्वारा संबंधित टेलीफोन विभाग से इसके स्वामित्व को सत्यापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए।

34. इस स्तर पर, यह अवलोकन करना उचित है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, सह-अभियुक्त मंटोश के इकबालिया बयान के आधार पर, मृतक का शव/कंकाल

पाया गया था। इसके अलावा, सह-अभियुक्त मंटोश के इकबालिया बयान के आधार पर, वर्तमान अपीलार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह विवाद में नहीं है कि उक्त सह-अभियुक्त मंटोश पर अलग से मुकदमा चलाया गया है क्योंकि वह किशोर था और वर्तमान अपीलार्थियों के मुकदमे को भी अलग कर दिया गया था। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध एकमात्र सामग्री सह-अभियुक्त मंटोश का इकबालिया बयान है जिसके आधार पर मृतक का कंकाल पाया गया था। सह-अभियुक्त द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध दिए गए इकबालिया बयान के प्रभाव की भी वर्तमान मामले में जांच की जानी है। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर, अपीलार्थियों के खिलाफ उपलब्ध किसी अन्य भौतिक साक्ष्य के अभाव में, अपीलार्थियों के खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश पारित किया जा सकता है या नहीं।

35. इस स्तर पर, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जिन पर अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निर्भरता रखी गई है, पर विचार करना चाहेंगे।

36. **रामानंद @ नंदलाल भारती** (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा संख्या 53 और 54 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

> 53. यदि जाँच अधिकारी का कहना है कि कि अभियुक्त अपीलार्थी ने अपनी मर्जी और इच्छा से हिरासत में रहते हुए यह बयान दिया कि वह उस स्थान पर ले जाएगा जहाँ उसने अपने खून से सने कपड़ों के साथ अपराध का हथियार छिपा रखा था, तो जाँच अधिकारी को सबसे पहले दो स्वतंत्र गवाहों को पुलिस स्टेशन में ही बुलाना चाहिए था। एक बार जब दो स्वतंत्र गवाह पुलिस स्टेशन में उनकी उपस्थिति में पहुंच जाते हैं, तो आरोपी को उस स्थान की ओर इशारा करने के संबंध में एक उचित बयान देने के लिए कहा जाना चाहिए जहां उसने अपराध के हथियार को छिपाया था। जब अभियुक्त अभिरक्षा

में रहते हुए दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाहों) के समक्ष ऐसा बयान देता है तो अभियुक्त द्वारा दिए गए सटीक बयान या सटीक शब्दों को पंचनामे के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए जो जाँच अधिकारी कानून के अनुसार निकाल सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के उद्देश्य के लिए पंचनामे का यह पहला भाग हमेशा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस स्टेशन में तैयार किया जाता है ताकि यह विश्वास दिलाया जा सके कि अभियुक्त द्वारा एक विशेष बयान अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए दिया गया था, और उस स्थान को इंगित करने की इच्छा व्यक्त की थी जहां अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार या कोई अन्य वस्तु छिपी हुई थी। एक बार पंचनामे का पहला भाग पूरा हो जाने के बाद पुलिस दल आरोपी और दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाह) के साथ उस विशेष स्थान पर आगे बढ़ेगा जिसका नेतृत्व आरोपी कर सकता है। यदि उस विशेष स्थान से अपराध का हथियार या खून से सने कपड़े या कोई अन्य वस्तु मिलती है तो पूरी प्रक्रिया का वह हिस्सा पंचनामे का दूसरा भाग होगा। इस तरह कानून जांच अधिकारी से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत विचार के अनुसार खोज पंचनामा बनाने की उम्मीद/अपेक्षा करता है। यदि हम जाँच अधिकारी के पूरे मौखिक साक्ष्य को पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट है कि मामले के सभी उपरोक्त प्रासंगिक पहलुओं में इसकी कमी है।

54. हम खोज के साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए तैयार या अनिच्छुक होने का कारण यह है कि जांच अधिकारी ने अपने मौखिक साक्ष्य में पुलिस स्टेशन में आरोपी द्वारा कहे गए सटीक शब्दों के बारे में नहीं कहा है। खोज के साक्ष्य को खारिज करने का दूसरा कारण यह है कि जांच अधिकारी खोज पंचनामे की सामग्री को साबित करने में विफल रहे हैं। साक्ष्य

को खारिज करने का तीसरा कारण यह है कि भले ही जांच अधिकारी के पूरे मौखिक साक्ष्य को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन इसमें छिपाने के लेखन की कमी है। खोज के साक्ष्य को खारिज करने का चौथा कारण यह है कि हालांकि पंच गवाहों में से एक अ.सा.-2, छतरपाल रैदास का मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच की गई थी, फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा है कि उसने अपराध के हथियार और खून से सने कपड़ों की खोज के उद्देश्य से पंच गवाह के रूप में भी काम किया था। दूसरे पंच गवाह, अर्थात् प्रताप, हालांकि उपलब्ध थे, से अभियोजन पक्ष ने किसी कारण से पूछताछ नहीं की। इसलिए, अब हमारे पास जांच अधिकारी के साक्ष्य बचे हैं, जहां तक अपराध के हथियार और खून से सने कपड़ों की खोज का संबंध है, जैसा कि परिस्थितियों के दोषपूर्ण टुकड़ों में से एक है। हम कानून की स्थिति से अवगत हैं कि भले ही खोज पंचनामे के स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं की जाती है या खोज के समय कोई गवाह मौजूद नहीं था या यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं था, तो कानून के प्रस्ताव के रूप में यह निर्धारित करना मुश्किल है कि पुलिस अधिकारी द्वारा इस तरह से तैयार किए गए दस्तावेज़ को दूषित माना जाना चाहिए और खोज साक्ष्य को अविश्वसनीय और संदिग्ध माना जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय को जांच अधिकारी के साक्ष्य पर विचार करना पड़ता है, जिसने आरोपी से उसके स्वयं के मूल्य पर प्राप्त बयान के आधार पर खोज के तथ्य पर गवाही दी थी। "

37. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए उपरोक्त अवलोकन से, यह कहा जा सकता है कि जब अभियुक्त ने अपना इकबालिया बयान देने की इच्छा दिखाई है, तो यह जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह दो स्वतंत्र गवाहों को पुलिस स्टेशन में ही बुलाए और

स्वतंत्र गवाहों के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद, उनकी उपस्थिति में, आरोपी से एक उपयुक्त बयान देने के लिए कहा जाना चाहिए, जैसा कि वह स्थान को इंगित करने के संबंध में चाह सकता है जहां कहा जाता है कि उसने अपराध का हथियार छिपाया था। इसके अलावा, जब अभिरक्षा में अभियुक्त दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाहों) के समक्ष ऐसा बयान देता है, तो अभियुक्त द्वारा दिए गए सटीक बयान या सटीक शब्दों को पंचनामे के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए जो अनुसंधानकर्ता कानून के अनुसार तैयार कर/निकाल सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजन के लिए पंचनामा का यह पहला भाग हमेशा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस स्टेशन में तैयार किया जाता है ताकि यह विश्वास हो सके कि एक विशेष बयान अभियुक्त द्वारा उसके अपने स्वतंत्र इच्छा से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए दिया गया था और उस स्थान को इंगित करने की इच्छा जहां अपराध करने में उपयोग की गई वस्तु को छिपाया गया है। एक बार पंचनामे का पहला भाग पूरा हो जाने के बाद, पुलिस दल अभियुक्त और दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाह) के साथ उस विशेष स्थान पर जाएगी जैसा कि आरोपी द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। यदि उस विशेष स्थान से अपराध का हथियार या खून से सने कपड़े या कोई अन्य वस्तु मिलती है तो पूरी प्रक्रिया का वह हिस्सा पंचनामे का दूसरा भाग होगा जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के तहत विचार किया गया है।

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि जांच अधिकारी के पूरे मौखिक साक्ष्य में, उन्होंने उपरोक्त पहलुओं के बारे में खुलासा नहीं किया था और, इसलिए, सह-अभियुक्त मंटोश द्वारा किए गए खोज के साक्ष्य के संबंध में अभियोजन पक्ष का सिद्धांत संदेह पैदा करता है और इकबालिया बयान के आधार पर खोज विधिवत साबित नहीं होती है।

39. अन्यथा भी, वर्तमान कार्यवाही में, हम सह-अभियुक्त मंटोश के मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष का मामला है कि सह-अभियुक्त मंटोश के इकबालिया बयान

के आधार पर, वर्तमान अपीलार्थियों को फंसाया गया है। इस प्रकार, इस स्तर पर, हम इस बिंदु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का भी उल्लेख करना चाहेंगे कि क्या सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान वर्तमान अपीलार्थियों को बाध्य कर सकता है या नहीं और किस हद तक।

40. **हरिचरण कुर्मी** (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दिया गया इकबालिया बयान जो आपराधिक मुकदमे में भूमिका निभा सकता है, इस सवाल का निर्धारण साक्ष्य अधिनियम की धारा-30 के प्रावधानों के आलोक में किया जाना चाहिए। यह भी देखा गया है कि धारा-30 में यह प्रावधान है कि जब एक से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए एक साथ मुकदमा चलाया गया है और एक व्यक्ति द्वारा खुद को और ऐसे व्यक्तियों में से कुछ अन्य को प्रभावित करने के लिए की गई स्वीकारोक्ति साबित हो जाती है, तो न्यायालय ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ-साथ ऐसा स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी ऐसी स्वीकारोक्ति पर विचार कर सकता है। यह आगे देखा गया है कि एक स्वीकारोक्ति को सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है जो सह-आरोपी व्यक्ति के खिलाफ ठोस सबूत है। आपराधिक मामले से निपटने में जहां अभियोजन पक्ष एक अभियुक्त व्यक्ति के दूसरे अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ स्वीकारोक्ति पर निर्भर करता है, अपनाए जाने का उचित दृष्टिकोण ऐसे अन्य अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ अन्य साक्ष्य पर विचार करना है और यदि उक्त साक्ष्य संतोषजनक प्रतीत होता है और न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के लिए इच्छुक है कि उक्त साक्ष्य उक्त/उस अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ बनाए/लगाए गए आरोप को कायम रख सकता है, तो न्यायालय इस दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित करने के लिए उस स्वीकारोक्ति की ओर रुख करता है कि जिस निष्कर्ष पर यह अन्य साक्ष्यों से पहुंचने के लिए इच्छुक है, वह सही है।

40.1. **सुब्रमण्य** (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 63 से 67 में उपरोक्त पहलू पर विचार किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य

रूप से कहा है कि धारा 30 में, हालांकि, यह प्रावधान करती है कि न्यायालय स्वीकारोक्ति पर विचार कर सकता है और इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह ऐसा सबूत है जिस पर न्यायालय कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इस धारा ने यह नहीं कहा कि स्वीकारोक्ति सबूत के बराबर थी। समान रूप से, मामले में साबित सभी तथ्यों पर विचार करने के लिए अन्य साक्ष्य और स्वीकारोक्ति या केवल एक तत्व होना चाहिए जिसे पैमाने में रखा जा सकता है और अन्य साक्ष्य के साथ तौला जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि आपराधिक मुकदमे में नैतिक दोषसिद्धि या गंभीर संदेह के सिद्धांत को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा, आपराधिक मामलों में जहां अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ समर्पित अन्य साक्ष्य पूरी तरह से असंतोषजनक हैं और अभियोजन पक्ष सह-अभियुक्त व्यक्ति के स्वीकारोक्ति पर भरोसा करना चाहता है, निर्दोषता का धारणा/अनुमान, जो अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक न्यायशास्त्र का आधार है और न्यायालय को यह निर्णय देने के लिए मजबूर करता है कि आरोप उसके खिलाफ साबित नहीं हुआ है और इसलिए वह संदेह का लाभ उठाने का हकदार है।

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों और साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाता है, तो यह पता चलेगा कि वर्तमान दो अपीलार्थियों पर अलग-अलग मुकदमे में मुकदमा चलाया गया है और इसलिए, सह-अभियुक्त मंटोश के इकबालिया बयान को वर्तमान अपीलार्थियों के खिलाफ सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है। अन्यथा भी, वर्तमान मामले में, सह-अभियुक्त मंटोश के इकबालिया बयान को छोड़कर, वर्तमान अपीलार्थियों को विचाराधीन घटना से जोड़ते हुए अभिलेख पर कोई अन्य साक्ष्य नहीं उपलब्ध है। यहां तक कि अपीलार्थी मुकेश पासवान के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा समर्पित अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत पर भी हमारे द्वारा ऊपर की गई चर्चा को देखते हुए विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा,

जहां तक अपीलार्थी सुरेंद्र कुमार @ गोरे लाल का संबंध है, कथित घटना के साथ उक्त अपीलार्थी को जोड़ने का कोई सबूत नहीं है।

42. इस प्रकार, हमारा विचार है कि अभियोजन उन परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है जिनसे यह कहा जा सकता है कि वर्तमान अपीलार्थियों ने कथित अपराध किया है।

43. **शरद बिर्धिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य** के मामले में, **(1984) 4 एस.सी.सी. 116** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 152 और 153 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

> "152. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः
>
> (1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।
>
> यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य होनी चाहिए या होनी चाहिए' स्थापित किया जाना चाहिए, न कि 'हो सकता है'। 'सिद्ध हो सकता है' और 'सिद्ध होना चाहिए या होना चाहिए' के बीच न केवल एक व्याकरणिक बल्कि एक कानूनी अंतर हो सकता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एस.सी.सी. 793 : (ए.आई.आर. 1973 एस. सी. 2622) में अभिनिर्धारित किया गया था, जहाँ अवलोकन किए गए थेः
>
> "निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल

दोषी हो सकता है और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निश्चित निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होना चाहिए।

153. ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं। "

44. इस स्तर पर, हम संहिता की धारा-313 के तहत अभियुक्त के आगे के बयान की रिकॉर्डिंग के संबंध में अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क पर भी विचार करना चाहेंगे। संहिता की धारा-313 के तहत उनका बयान दर्ज करते समय, अपीलार्थियों/अभियुक्तों से केवल दो प्रश्न पूछे गए थे जो इस प्रकार हैंः

"1. आपके खिलाफ सबूत है कि 30.09.2016 को, आपने सुचक के बेटे रौशन कुमार का गांव जगन्नाथपुर (कल्याणपुर), पुलिस स्टेशन विभूतिपुर से हत्या और फिरौती के इरादे से अपहरण कर लिया, और 01.10.2016 को,

आपने 15 लाख रुपये की फिरौती की मांग की और धमकी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अपहृत व्यक्ति को मार दिया जाएगा?

2. आपके खिलाफ यह भी सबूत है कि 01.10.2016 को, आपने सह-अभियुक्त के साथ, समान इरादे को आगे बढ़ाते हुए, गोवाड़ी चौर में भगवान कुआँ के पश्चिम में गन्ने के खेत में अपहृत रौशन की हत्या कर दी और सबूतों को नष्ट करने के इरादे से शव को फेंक दिया?"

45. अब, इस स्तर पर, हम इस मामले में **राज कुमार @सुमन बनाम राज्य (दिल्ली का एन. सी. टी.), 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 609** में प्रकाशित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को संदर्भित करना चाहेंगे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा संख्या 10 से 13 में संहिता की धारा 313 में निहित प्रावधानों की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा की है। मुख्य रूप से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि संहिता की धारा-313 का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। यदि साक्ष्य में एक बिंदु अभियुक्त के खिलाफ महत्वपूर्ण है, और दोषसिद्धि उसी के आधार पर होने का इरादा है, यह सही और उचित है कि अभियुक्त से मामले के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए और उसे समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए। अभियुक्त के खिलाफ पेश होने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग से उसके सामने रखा जाना आवश्यक है। ऐसा करने में विफलता एक गंभीर अनियमितता के बराबर है जो मुकदमे को दूषित करती है यदि यह दिखाया जाता है कि इस कारण आरोपी पूर्वाग्रहित हुआ है।

46. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, यदि न्यायालय द्वारा अभियुक्तों से पूछे गए प्रश्न/अपराधजन्य परिस्थिती की सावधानीपूर्वक जांच की जाए, तो यह पता चलता है कि सह-अभियुक्त मंतोष के इकबालिया बयान की

परिस्थिति जिसके आधार पर मृतक के कंकाल/शरीर की तथाकथित खोज की गई थी, अभियुक्तों के समक्ष नहीं रखी गई। इसके अलावा, अपीलकर्ता/अभियुक्त मुकेश पासवान को संबंधित गवाहों द्वारा मृतक रौशन के साथ साइकिल पर अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति भी उक्त अभियुक्त/अपीलकर्ता के समक्ष नहीं रखी गई।

47. इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अभियोजन पक्ष का यह विशिष्ट मामला है कि अ.सा. 1 से 4 के माध्यम से उन्होंने मृतक को अपीलकर्ता मुकेश के साथ साइकिल पर आखिरी बार देखा था। हालाँकि, यह परिस्थिति भी उसके सामने नहीं रखी गई। इस स्तर पर, यह देखना आवश्यक है कि अ.सा. 1 से अ.सा. 4 के माध्यम से अभियोजन पक्ष का यह विशिष्ट मामला है कि उन्होंने मृतक को अंततः अपीलार्थी मुकेश के साथ साइकिल पर देखा था। हालाँकि, वह परिस्थिति भी उनके सामने नहीं रखी गई।

48. यह बचाव पक्ष का विशिष्ट मामला है कि अपीलार्थियों की संहिता की धारा-313 के तहत बयान दर्ज करते समय की गई उपरोक्त घोर अवैधता/अनियमितता के कारण, उनके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है और वे अदालत को उक्त परिस्थितियों को समझाने के अवसर से वंचित थे।

49. इस प्रकार, अभियोजन-गवाहों के उपरोक्त बयान से, हमारा विचार है कि अभियोजन-गवाहों के बयान में बड़े विरोधाभास और सुधार हैं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष वर्तमान मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है।

50. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों/अभियुक्तों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद निचली अदालत ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश का आक्षेपित निर्णय दर्ज किया है। इस प्रकार, उसे अपास्त और निरस्त करने की आवश्यकता है।

51. तदनुसार, दिनांकित 12.12.2018 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश दोनों को रद्द और निरस्त किया जाता है। अपीलार्थीयों को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

51.1. दोनों याचिकाकर्ता अभिरक्षा में हैं। यदि किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें तुरंत जेल अभिरक्षा से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

52. दोनों अपीलों को स्वीकार किया जाता है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

के.सी.झा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।